भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 61
गुरुवार, 07 दिसंबर, 2023/16 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमान किरायों में जारी वृद्धि

***61. श्रीमती संगीता आज़ाद:**
श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर:
क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को घरेलू विमान किरायों में तीस प्रतिशत तक की वृद्धि होने की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा हवाई टिकट की ऊंची कीमतों से संबंधित समस्याओं को दूर करने और यात्रियों के लिए वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) अत्यधिक मूल्य वृद्धि को रोकने और एयरलाइनों के बीच न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए बनाई गई दीर्घकालिक कार्यनीतियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की विमान कंपनियों की वित्तीय व्यवहार्यता और यात्रियों को अधिक विमान किरायों की समस्या झेलने से रोकने के बीच संतुलन बनाने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की आगामी वर्षों में विमान किरायों के सम्बन्ध में ग्राउंडेड विमानों और आपूर्ति संबंधी चुनौतियों के प्रभाव से निपटने और विमान किरायों को स्थिर करने की योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ङ) तक: एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"विमान किरायों में जारी वृद्धि" के संबंध में लोक सभा के दिनांक 07.12.2023 के तारांकित प्रश्न संख्या 61 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ग) मौजूदा विनियमों के अनुसार, सरकार द्वारा हवाई किराए न तो निर्धारित किए जाते हैं और न ही विनियमित किए जाते हैं। वायुयान नियमावली, 1937 के नियम 135 के उप नियम (1) के प्रावधान के तहत, अनुसूचित हवाई सेवाओं में प्रवृत्त, प्रत्येक हवाई परिवहन उपक्रम द्वारा, प्रचालन की लागत, सेवाओं की विशेषता और आम तौर पर प्रचलित

टैरिफ सहित, सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ निर्धारित करना अपेक्षित है।

एयरलाइन मूल्य निर्धारण प्रणाली कई स्तरों (बकेट या आरबीडी) में है, जो वैश्विक स्तर पर अपनाई जा रही परिपाटियों के अनुरूप हैं। किरायों का निर्धारण, एयरलाइनों द्वारा, बाजार, मांग, मौसम और बाजार के अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। सीटों की मांग में वृद्धि होने पर हवाई किराया बढ़ जाता है क्योंकि किराया बकेट में कम किराए वाली सीटें शीघ्र ही बिक जाती हैं और उसके बाद किराया बकेट में अधिक किराए वाली सीटें ही उपलब्ध रहती हैं।

विभिन्न देशों में हवाई किराए गतिक स्वरूप के होते हैं और मांग और आपूर्ति के बाजार सिद्धांत का पालन करते हैं। किराए कई अन्य कारकों जैसे किसी विशेष उड़ान पर पहले से ही बेची गई सीटों की संख्या, ईंधन की मौजूदा कीमत, मार्ग पर प्रचालन करने वाले विमान की क्षमता, क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, मौसम, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये का मूल्य, छुट्टियाँ, त्योहार, लंबे वीकेंड, कार्यक्रम (खेल, मेले, प्रतियोगिताएं) आदि पर भी निर्भर करते हैं।

विश्व स्तर पर, अधिकांश देशों ने अपने विमानन क्षेत्र को नियंत्रणमुक्त कर दिया है, अर्थात एयरलाइनों पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रवेश और मूल्य प्रतिबंधों को हटाना। अविनियमन के कारण एयरलाइन वाहकों की आपस में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, जिससे हवाई किराया कम हो गया है। अविनियमन के परिणामस्वरूप, संभावित नई एयरलाइन के लिए एयरलाइन उद्योग में प्रवेश सरल हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप कई नई एयरलाइनें इस बाजार में प्रवेश कर रही हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। अविनियमन का सीधा असर यह है कि कम आय वर्ग का यात्री, हवाई यात्रा कर सकता है।

मंत्रालय ने एयरलाइनों के साथ परामर्श किया था और प्रतिनिधियों को सलाह दी गई थी कि वे हवाई किराया तय करते समय स्व-विनियमन करें और यात्रियों के हित को ध्यान में रखें।

एयरलाइनों को भी मूल्य निर्धारण में संयम बरतने और यात्रियों के हित को ध्यान में रखने के लिए संवेदनशील बनाया गया है। एयरलाइनें यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं आदि जैसी घटनाओं के दौरान हवाई किराए में वृद्धि न हो।

भारतीय विमानन उद्योग की जटिल गतिशीलता को देखते हुए, सरकार इस क्षेत्र के विकास को समर्थन देने के लिए अनुकूल माहौल बनाकर एक सुविधाप्रदाता की भूमिका निभा रही है।

(घ) एवं (ङ) नागर विमानन महानिदेशालय ने भारतीय प्रचालकों को ओवरहॉल्ड इंजन उपलब्ध कराने के लिए, प्रैट एंड व्हिटनी के साथ मामले पर विचार-विमर्श किया है और निर्माता को उनकी रखरखाव क्षमता बढ़ाने की सलाह दी है। नागर विमानन महानिदेशालय इंजन विनिर्माता के साथ लगातार मामले पर नजर बनाए हुए है।

भले ही आज की तारीख में, विमान प्रचालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुल परिचालन बेड़ा नवंबर, 2022 में 622 से बढ़कर नवंबर, 2023 में 643 हो गया है।

सरकार एयरलाइनों को प्रोत्साहित कर रही है कि वे वाइड-बॉडी विमान सहित, अन्य विमान खरीदें और अधिक उड़ानें प्रचालित करें जिससे मांग-आपूर्ति की स्थिति नियंत्रित हो जाएगी। जैसे-जैसे क्षेत्र का विकास होगा, उद्योग में और अधिक विमान शामिल किए जाएंगे जिससे आपूर्ति की स्थिति बढ़ेगी और इसका हवाई किराए पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

******